

घाटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



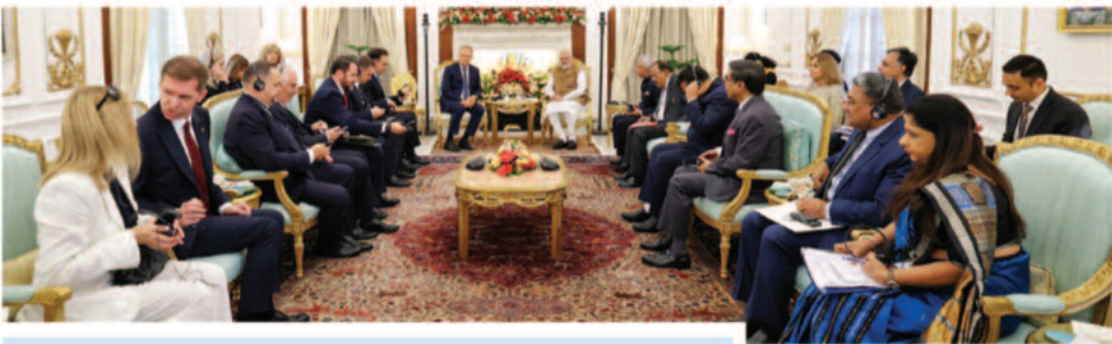
www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर, तर्ष 22, अंक - 349- शुक्रवार 23- अक्टूबर 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत-पोलैंड के बीच रक्षा, अंतरिक्ष व परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति...

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और पोलैंड ने रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ़ करने पर सहमति जताई है। उन्होंने इन क्षेत्रों में सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए पोलैंड की कंपनियों को भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्ता हुई। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस वक्तव्य दिया। मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए अवसरों को व्यापक बनाया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत करते हुए मोदी ने कहा कि वर्ष 2024 में उनकी पोलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसी मजबूत आधार पर पिछले दो वर्षों में द्विपक्षीय साझेदारी ने नई गति हासिल की है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत ने भी दोनों देशों के बीच सहयोग की नई संभावनाएं पैदा की हैं। मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड के संबंध केवल कूटनीतिक संघर्षों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मानवता और संवेदना की साझा विरासत पर



व्यापार दोगुना करेंगे भारत-पोलैंड, दुर्लभ खनिज में करेंगे सहयोग

भारत और पोलैंड 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करेंगे। पोलैंड भारत की पहल 'कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर' से जुड़ेगा। दोनों देश रक्षा उद्योग तथा आतंकवाद विरोधी संवाद स्थापित करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार के दोगुना होने से रोजगार सृजन और नए अवसर बढ़ेंगे। विकास, निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा संवाद स्थापित होने से क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ेगा। इसके माध्यम से दोनों देश विकास एवं सह-उत्पादन से जुड़े अवसर तलाशेंगे। रक्षा क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और रक्षा सप्लाइ चैन मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच गुरुवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। वार्ता को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी में एक नया चरण है। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के महत्व पर जोर दिया।

आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जामनगर और कोल्हापुर के राजपरिवारों ने पोलैंड के हजारों बच्चों और परिवारों को भारत में आश्रय दिया था। उन्होंने सांस्कृतिक और जनस्तरिय संघर्षों को दोनों देशों के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि पोलैंड में संस्कृत अध्ययन और संस्कृतिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने का प्रयास है। भारत और पोलैंड लोकतांत्रिक मूल्यों में भारतीय अध्ययन पीठ की स्थापना भी इसी सांस्कृतिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने का प्रयास है। भारत और पोलैंड लोकतांत्रिक मूल्यों तथा कानून के शासन में विश्वास रखते हैं। दोनों देश वैश्विक शासन संस्थाओं को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए उनके सुझावों की जरूरत है।



प्रत्येक भव्य रसायन पार्क को केंद्र सरकार देगी 1000 करोड़ की सहायता

केंद्रीय मंत्री नड्ड ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भव्य रसायन पार्क के निर्माण के लिए हमें एक-एक हजार करोड़ रुपये (प्रति रसायन पार्क) की बड़ी धनराशि मिल रही है। केन्द्र सरकार ने इस योजना को अपने बजट में शामिल कर लिया है। विश्वस्तरीय भव्य रसायन पार्क विकसित करने के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियां भी केंद्र सरकार ही दिलाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोकेमिकल सेक्टर में पहले से स्थापित राज्यों को भी पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। केन्द्र सरकार ने एडवांस पेट्रोकेमिकल और केमिकल सेक्टर में शोध और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के फंड डेवलपमेंट का प्रावधान किया है। नीति आयोग ने पेट्रोकेमिकल और केमिकल को प्रमुख चार सेक्टर में शामिल किया है।

सोनिया गांधी पहली बार सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया...नई किताब का वीडियो शेयर किया, यह 10 नवंबर को लॉन्च होगी

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने गुरुवार को पहली बार अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। उन्होंने अपनी पहली पोस्ट में आने वाली किताब 'Belonging: A Journey of Love' का वीडियो शेयर किया। यह किताब 10 नवंबर को लॉन्च होगी। सोनिया ने पहली पोस्ट गुरुवार सुबह 9 बजे की थी। इसमें लिखा कि नमस्कार, 'मैं अपनी किताब आप सभी के साथ साझा करके खुश हूँ। यह प्यार, करीब, अपनी को खोने और अपनेपन की जगह तलाशने की कहानी है। मैं इसे आप सबके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ।' वीडियो में सोनिया अपने करीबियों और बेटी प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही हैं। इस दौरान प्रियंका ने मां को मिठाई भी खिलाई। किताब में सोनिया ने इटली में बिताए बचपन से लेकर कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात तक का जिक्र किया है। इसमें नेहरू-गांधी परिवार में शादी और परिवार में हुई हत्याओं के बाद बदली जिंदगी के बारे में लिखा है। 'Belonging' की शुरुआत युद्ध के बाद इटली के वेनेटो क्षेत्र में सोनिया के बचपन से होती है। इसके बाद किताब में उनके कैम्ब्रिज जाने और 1965 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पोते राजीव गांधी से मुलाकात का जिक्र है। आत्मकथा में राजीव गांधी से उनकी शादी और अपनी सास, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात का भी वर्णन है। इसमें भारत में जीवन के साथ तालमेल बैठाने के उनके अनुभव शामिल हैं। इनमें हिंदी सीखना, साड़ी पहनना और भारतीय खानपान व संस्कृति को अपनाना भी शामिल है।



भारत-कनाडा के बीच शिक्षा और शोध सहयोग पर चर्चा, एमओयू को लागू करने पर जोर

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। भारत और कनाडा के बीच शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई है। शिक्षा मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च शिक्षा के संबंधों को फिर से मजबूत करने, शोध साझेदारी का विस्तार करने और छात्रों के लिए एक-दूसरे के देश में पढ़ाई के अवसर बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत में कनाडा के उच्चयुक्त क्रिस्टोफर कूटन और ट्रेड कमिशनर एमी एंटोनिनो के साथ शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई बातचीत के दौरान घोषित समझौता ज्ञापनों को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में भारत और कनाडा के शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने और शोध के क्षेत्र में नई साझेदारियां विकसित करने पर विचार किया गया। दोनों देशों के बीच छात्रों की आवाजाही को आसान बनाने और उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, भारत में कनाडा के विश्वविद्यालयों के लिए अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कनाडा के विश्वविद्यालयों को भारत में मौजूदगी और उनके लिए सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत हुई।



वाराणसी में एयरशो 'विंग्स ओवर गंगा' के पहले दिन दिखा रोमांच, वायुसेना ने मोहा मन एयर शो में शामिल होने वाले विमान देशभर के 12 वायु अड्डों से भर्से उड़ान...

वाराणसी, 22 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी काशी में भारतीय वायुसेना के 94 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय एयर शो 'विंग्स ओवर गंगा' का आगाज रोमांच और उत्साह के बीच हुआ। गुरुवार को पहले दिन गंगा की लहरों के ऊपर आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना, तेज रफ्तार उड़ान और हैरतअंगेज कलाबाजियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। काशी में पहली बार इस तरह के हवाई प्रदर्शन को देखने के लिए युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। सुबह 10 बजे से ही लोग घाटों पर जुटने लगे और गंगा के दोनों तटों पर दर्शकों की भीड़ दिखाई दी। एयर शो के मुख्य आयोजन से पहले नमोघाट और आरुपारस के घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आसमान में विमानों की कतारबद्ध उड़ान, सटीक



तालमेल और रोमांचक हवाई करतबों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। भारतीय वायुसेना की परिकालन क्षमता, तकनीकी दक्षता और सामरिक ताकत का प्रदर्शन देखकर लोग प्रभावित नजर आए। शुरुआत नमोघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से हुई। एयर शो में केदार, सारंग, ओंकार, गंगा, रुद्र, भागीरथी, त्रिवेद, अलकनंदा, भैरव, कैलाश, त्रिलोचन और दशरथवर्मन सहित विभिन्न नामों पर आधारित हवाई फॉर्मेशन

आकर्षण का केंद्र रहे। विमानों ने अनुशासित उड़ान, सटीक समन्वय और शानदार हवाई युद्धाभ्यास के जरिए वायु योद्धाओं की पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया। इस आयोजन में भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से फॉर्मेशन तैयार किए गए हैं। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम के करतब भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहे। इसके अलावा ऐतिहासिक हवाई विमान की मौजूदगी ने एयर शो की शोभा बढ़ाई। हवाई प्रदर्शन में कुल 100 विमानों की भागीदारी निश्चित है। इनमें 52 लड़ाकू विमान, 15 परिवहन विमान, 32 हेलीकॉप्टर और एक ऐतिहासिक विमान शामिल हैं।



स्तर पर सक्रिय नेटवर्क की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने फॉक्स न्यूज की डिजिटल जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि फ्रांस समेत कई देशों में 'रेजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन के लिए अराजकता और विरोध प्रदर्शनों

का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों के तार भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ते हैं। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को गैर-जिम्मेदार और अपरिपक्व बताया और उनके लिए 'गद्दार' और 'मीर जाफर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के नेता प्रतिपक्ष से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में नौ देशों में सक्रिय 101 संगठनों के नेटवर्क का उल्लेख किया गया है, जिसे 'रेड-ग्रीन इकोसिस्टम ऑफ प्रोटेस्ट' कहा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नेटवर्क के जरिए निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। हालांकि, इन आरोपों और कथित नेटवर्क की भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

माप से राज्यसभा की रिक्त एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान 12 नवंबर को होगा मतदान

भोपाल, 22 अक्टूबर 2026। राज्यसभा से डॉ. एल मुरगन के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश से रिक्त हुई एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। इस सीट पर 12 नवंबर को मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी।

डॉ. एल. मुरगन सरकार में मंत्री भी थे। वे 3 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बने थे, उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था, लेकिन उन्होंने 14 अक्टूबर को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के साथ ही राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट रिक्त हो गई।

अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनरुद्धार से जुड़ी 8,941 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया...

यमुनोत्री से लेकर संगम तक यमुना को स्वच्छ करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिलने वाला है : अमित शाह



और हर रोज डेयरियों का 2000 टन गोबर यमुना में डालने का काम किया। एक जमाने में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल के सहयोगी दलों की सरकारों की पार्टी की सरकार बनते ही एक बड़ी बैठक बुलाकर यमुना को शुद्ध करने की अपनी संकल्पना दिल्ली सरकार और देश के गृह मंत्रालय के सामने रखी थी। इतने कम समय में हमने 40 प्रतिशत से अधिक सफलता प्राप्त कर ली है। अमित शाह ने कहा कि 30 साल से पिछली सरकारों ने दिल्ली के गटर के पानी को यमुना में छोड़ने

समयबद्ध रोडमैप बनाए हैं जिसके माध्यम से हम 2029 तक यमुना को निर्मल बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दिल्ली बनाना चाहते हैं, जहां घर सुंदर हों, पानी शुद्ध हो, गलियां साफ हों, कूड़े के पहाड़ न हों और यमुना निर्मल होकर यहां से संगम तक की जनता को अपना आशीर्वाद दे सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस काम को एक अडिग संकल्प के रूप में लिया है और आज इस संकल्प के एक बहुत बड़े भाग की पूर्ति हो रही है। उन्होंने

कहा कि यहां 10 योजनाओं का लोकार्पण हुआ और 33 योजनाओं की शुरुआत हुई है। 8,941 करोड़ की कुल लागत से शुरू हुई योजनाओं के माध्यम से कई लाख लीटर पानी शुद्ध होकर यमुना में जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों से जुड़ी परियोजनाओं का आज यहां लोकार्पण हुआ है।

कैजरीवाल ने यमुना में डुबकी लगाने का झूठ वाद किया : अमित शाह

गृह मंत्री ने कहा, 'कैजरीवाल जी आपने 3 बार यमुना में डुबकी लगाने का झूठ वाद किया। आपने तो डुबकी नहीं लगाई लेकिन आपके कटआउट को डुबकी लगवाई तो वो भी बीमार हो गया और एप्स में भर्ती करना पड़ा। यमुना के शुद्धिकरण के लिए आपने कुछ काम नहीं किया...विश्व स्तरीय काम भाजपा की सरकार ने किया है और 3 साल का एक एक्शन प्लान हमने बनाया है। हम दिल्ली के हर घर को गटर के पानी के सीवेज का कनेक्शन देंगे और हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम भी भाजपा करेगी।' अमित शाह ने आगे कहा, 'कुछ राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो बहाने की राजनीति करती हैं। इससे पहले आप पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वो बहाने बनाते थे कि हमें यह मदद नहीं मिली, वह मदद नहीं मिली। कैजरीवाल जी मेरे पास आपकी हर बात का जवाब है मगर मैं जवाब तब दूंगा जब पंजाब में भी आप सरकार को हम उखाड़कर फेंक देंगे। अपने आंदोलन के नाम पर सत्ता हथियारक भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। कूड़े के पहाड़ों के नाम पर राजनीति करते रहे और हमने कूड़े के पहाड़ों को नीचे लाने का काम किया है।

कहा कि यहां 10 योजनाओं का लोकार्पण हुआ और 33 योजनाओं की शुरुआत हुई है। 8,941 करोड़ की कुल लागत से शुरू हुई योजनाओं के माध्यम से कई लाख लीटर पानी शुद्ध होकर यमुना में जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों से जुड़ी परियोजनाओं का आज यहां लोकार्पण हुआ है।

उत्तराखंड में मदरसों की धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बदला...धामी बोले-हिंसा से जुड़ी सामग्री को जगह नहीं

देहरादून, 22 अक्टूबर 2026। उत्तराखंड सरकार ने मदरसों में धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए नए मानक निर्धारित किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए पाठ्यक्रम में हिंसा, नफरत और कट्टरवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में ऐसी नई पीढ़ी तैयार करना है, जो प्रेम, सद्भाव और राष्ट्रसेवा की भावना के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने इससे पहले मदरसों में गुरुवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया था। इसके बाद मदरसा बोर्ड के स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया।

सरकार के अनुसार, अब पंजीकृत मदरसों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों की पढ़ाई अनिवार्य है। धार्मिक शिक्षा के लिए भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करने के बाद अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है। सभी मदरसों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार प्राधिकरण और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा, इसके लिए भी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं।

काँकरोच जनता पार्टी नेता सौरव-आशुतोष दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं हुए... क्राइम ब्रांच से और समय मांगा, दीपके बोले...दोनों मुझसे बड़े नेता

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने काँकरोच जनता पार्टी (काँकरोच जनता पार्टी) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को गुरुवार को राजीवी गार्डन स्थित अपने ऑफिस में पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन दोनों पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने पुलिस से और समय मांगा है। पुलिस उन्हें नया नोटिस जारी करेगी। दोनों नेताओं को कल दिल्ली की स्पेशल एंजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी। दोनों को 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड पर रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दोनों को हिरासत में लिया था। काँकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सौरव और आशुतोष उनसे बेहतर और बड़े नेता हैं। अगर वे कुछ कहेंगे तो मैं उनकी बात मानूंगा। सरकार ने 12 अक्टूबर को जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया था। इसके बावजूद 13



अक्टूबर को आशुतोष और सौरव तिरंगा लेकर यहां पहुंच गए। शांति नियम तोड़ने के आरोप में उन्हें 5 दिन के लिए जेल भेजा गया था। फिर 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी गई थी। इससे पहले बुधवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि नेता पहले मजिस्ट्रेट का फैसला आने दें।

आर्थिक हितों पर चोट करते आंदोलन

लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को असहमति जताने और सरकार से जवाब मांगने का अधिकार है। पिछले कुछ अर्से से यदि कारोचर जनता पार्टी यानी सीजेपी और कुछ विपक्षी दलों को लगता है कि मात्र कुछ हजार लोगों के सहारे अराजकता फैला कर हर बात पर सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया जा सकता है तो यह शायद उनकी अपरिपक्वता ही है। सीजेपी नेताओं और विपक्षी दलों के प्रतिदिन लगभग 400 करोड़ रुपये के कारोबार के नुकसान का अनुमान व्यक्त किया। ऐसे में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती,जिसमें नागरिकों की आवाज भी सुनी जाए और देश की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित न हों। मुख्य सड़कों पर अराजकता या अव्यवस्था की आशंका भरे आंदोलन से न सिर्फ बाजार की बिक्री प्रभावित होती है,बल्कि इसका असर दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों,सामान पहुंचाने वाले वाहन चालकों,छोटे थोक व्यापारियों,पैकिंग करने वाले श्रमिकों,रेहड़ी-पटरी वाले और बासपास चाय आदि की दुकान चलाने वाले भी प्रभावित होते हैं।

अब कारोबारों तो कुछ समय तक नुकसान सह सकते हैं,लेकिन रोज की कमाई पर निर्भर परिवार के लिए एक दिन का काम छूटना भी भोजन,किराया,बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों के खर्च को प्रभावित करता है। बड़े त्योहारों और शदी-विवाह के समय में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। त्योहारों से पहले खुदरा व्यापारियों को उम्मीद रहती है कि कपड़े, जूते,इलेक्ट्रॉनिक्स,उपहार,मिठाइयों और घरेलू सामान की बिक्री बढ़ेगी। व्यापारी पहले से माल खरीदते हैं,कर्मचारियों की व्यवस्था करते हैं और किराया तथा अन्य खर्च वहन करते हैं। सड़कों पर अव्यवस्था या फिर अराजकता के कारण यदि ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पाते तो बाजार एवं आर्थिकी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे आंदोलन आर्थिक विकास, निवेश, उत्पादन और रोजगार के लिए भी मुश्किलें उत्पन्न करते हैं। वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित शोधपत्र ‘सामाजिक अशांति के व्यापक आर्थिक प्रभाव’ में 1990 से 2019 तक के विभिन्न देशों के आंकड़ों के आधार पर बताया गया था कि सामाजिक अशांति का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अशांति बढ़ने के छह तिमाहियों बाद भी जीडीपी का स्तर औसतन 0.2 प्रतिशत नीचे रह सकता है,जबकि अशांति की बड़ी घटनाओं के बाद यह अंतर लगभग एक प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इसका प्रमुख कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में गिरावट,उपभोग में कमी तथा निवेशकों के विश्वास में कमजोरी है। शोध में यह भी पाया गया कि कई आंदोलनों का आर्थिक प्रभाव राजनीतिक या चुनाव संबंधी आंदोलनों से अधिक हो सकता है। निरंतर अराजकता और अव्यवस्था देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित करती है।

आज जब विश्व की अनेक एजेंसियों ने भारत का जीडीपी अनुमान बढ़ा दिया है, तब संकीर्ण स्वाथों की पूर्ति के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए,जो आर्थिक माहील को नकारात्मक बनाए। नेताओं की यह समझना होगा कि अराजकता पैदा करने वाले आंदोलन लोगों का ध्यान आकर्षित करने का आसान रास्ता तो हो सकता है,पर लोकतंत्र मे सत्ता परिवर्तन केवल चुनावी जनमत,स्पष्ट नीतिगत विकल्पों और जन-विश्वास से ही संभव है। भारत में सड़कों पर अव्यवस्था सत्ता परिवर्तन का साधन नहीं बन सकती। आज देश का आम नागरिक अपनी आजीविका और बेहतर भविष्य को लेकर अधिक सजग है।यदि किसी कारण देश की अर्थव्यवस्था या रोजमर्रा का कारोबार बाधित होता है,तो आम जनता को यह अहसास होने लगता है कि आर्थिक अस्थिरता से देश और उनका खुद का नुकसान हो रहा है। इससे वे सत्ता परिवर्तन के बजाय शांति और स्थिरता के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आज का युवा और अनेक-अनेक मतदाता अधिक जागरूक है। वह भावनात्मक नारों से अधिक अपने आर्थिक भविष्य के आधार पर राजनीतिक निर्णय लेता है। आम तौर पर आंदोलनकारियों इसे भांप नहीं पाते कि आज लोग आर्थिक व्यवधान पैदा करने वाले किसी माध्यम को सकारात्मक बदलाव का जरिया नहीं मानते। आर्थिक दृष्टि से आदर्श लोकतंत्र वह है,जहां विरोध की आवाज भी सुनी जाए और अर्थव्यवस्था की गति भी बाधित न हो। जहां सरकार की जिम्मेदारी है कि वह असंतोष के कारणों को समझे और संवाद के माध्यम से समाधान निकाले,वहीं आंदोलनकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते समय आम लोगों की आजीविका और सार्वजनिक हितों का भी ध्यान रखें। प्रभावी संस्थाएं,संवेदनशील शासन और जिम्मेदार विरोध,इन तीनों के समन्वय से ही आर्थिक प्रगति और सवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

आखिर कब थमेगा धार्मिक आयोजनों में मौत का सिलसिला?

योगेश कुमार गोयल,नजफगढ़, नई दिल्ली धर्म,आस्था और विश्वास के केंद्रों पर ईसान सुकून,शांति और सुख-समृद्धि की कामना लेकर पहुंचता है लेकिन जब वही स्थान चीख-पुकार, दमघोटे, भीड़ और मौत के मंजर में तब्दील हो जाएं तो यह हमारी व्यवस्था की संवेदनहीनता और सुरक्षा संबंधी तैयारियों की विफलता का भयावह प्रमाण है। कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्तूबर की शाम भगदड़ जैसी स्थिति में 19 लोगों की मौत और दो दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया। सप्तमी की शाम मां दुर्गा के दर्शन की लातलास लेकर निकले श्रद्धालुओं को क्या पता था कि घर लौटने के बजाय कई परिवारों को अपने प्रियजनों के शव मिलेंगे? जिस उत्सव में जीवन,शक्ति और विजय का संदेश गुंजना चाहिए था,वहां मातम पसरा था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारी आस्था के स्थलों पर ईंसानी जड़ों इतनी क्यों हो जाती है? चोरबागान की घटना को केवल अचानक उमड़ी भीड़ या दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताकर जिम्मेदारी से बचना आसान है लेकिन ऐसा करना त्रासदी के वास्तविक कारणों से आंखें मूंदना होगा। बारिश के बीच पंडाल में प्रवेश और निकास के रास्तों पर भीड़ का दबाव बढ़ा और अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हुई। घटनास्थल की संकरी गलियों, लोगों की आवाजों तथा सुरक्षा प्रबंधों को लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि,दुर्घटना के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारी का निर्धारण निष्पक्ष जांच से ही होना चाहिए। फिर भी, यदि भारी भीड़ और खराब मौसम के बावजूद आवाजाही को सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तो यह गंभीर प्रशासनिक और आयोगजन संबंधी विफलता का मामला है। जब किसी आयोजन में हजारों लोगों के जुटने की संभावना पहले से मालूम

सूचना

समाचार पत्र में ऐसे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमार ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निरापरा अभिक्तापुर य्ग्यात्मल के अधीन होगा।

सम्पादक

लेख एवं विचार अभिव्यक्ति

जानलेवा होती हवा : सर्दियों से पहले ही प्रदूषण की चुनौती

सर्दियों ने अभी पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है कि देश के अनेक शहरों की हवा में प्रदूषण का जहर घुलने लगा है।

दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का तेजी से बिगड़ना इस बात का संकेत है कि प्रदूषण का संकट अब केवल

सर्दियों की मौसमी समस्या नहीं,बल्कि हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन,शहरी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती बन चुका है। हर साल अक्टूबर-नवंबर में दमघोड़े धुंध,आंखों में जलन,सांस लेने में कठिनाई और अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या के साथ यह संकट सामने आता है।

विडंबना यह है कि समस्या के कारणों की पहचान होने और उपायों की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद हम हर वर्ष उसी त्रासदी को दोहराने के लिए विवश दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि क्या स्वच्छ हवा में सांस लेना भी अब नागरिकों के लिए एक दुर्लभ सुविधा बनकर रह जाया? वायु प्रदूषण किसी एक कारण या किसी एक राज्य की देन नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन,निर्माण स्थलों से उड़ती धूल,सड़कों पर जमा मिट्टी,कचरा और जैविक पदार्थ जलाना,ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला उत्सर्जन तथा कृषि अवशेषों का दहन इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। सर्दियों में तापमान गिरने,हवा की गति कम होने और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण प्रदूषक जमीन के निकट जमा हो सकते हैं। इससे प्रदूषण

का प्रभाव अधिक गंभीर हो जाता है। इस प्रकार मौसम समस्या को बढ़ाता अवश्य है,लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाले मूल कारण मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उनके अपर्याप्त नियमन से जुड़े हैं।

दिल्ली-एनसीआर की स्थिति इस संकट का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। दिल्ली के साथ गाजिया बाद,नोएडा, ग्रे ट र नोएडा,गुरुग्राम,फरीदाबाद और आसपास के अनेक शहर एक-दूसरे से जुड़े वायु क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसलिए केवल दिल्ली की सीमाओं के भीतर उपाय करने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। हवा किसी प्रशासनिक सीमा को नहीं मानती,वह प्रदूषण को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाती है।अतः समाधान भी क्षेत्रीय सहयोग,साझा जवाबदेही और समन्वित कार्ययोजना पर आधारित होना चाहिए। वायु प्रदूषण का सबसे भयावह पक्ष उसका स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है। विशेष रूप से पीएम 2.5 जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में रक्तप्रवाह तक प्रवेश कर सकते हैं। इनके लंबे समय तक संपर्क में रहने से हृदय एवं फेफड़ों संबंधी बीमारियों,स्ट्रोक और समस्यापूर्ण मृत्यु का जोखिम बढ़ता है। बच्चों,बुजुर्गों,गर्भवती महिलाओं तथा किशोरों के बमरंग लोगों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है।

यह संकट केवल सांस के मरीजों



तक सीमित नहीं है। स्वस्थ दिखाई देने वाले लोगों की कार्यक्षमता,एकग्रता और जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को खुले मैदान में खेलने से रोकना पड़े,बुजुर्ग सुबह की सैर छोड़ने को विवश हों और श्रमिकों को जहरीली हवा में काम करना पड़े,तो यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं,बल्कि जीवन की गरिमा और नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है। एयर प्यूरीफायर या मास्क कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत बचाव में सहायक हो सकते हैं,लेकिन वे स्वच्छ हवा की सार्वजनिक व्यवस्था का विकल्प नहीं बन सकते। प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेडेड रिसॉर्स एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध,वाहनों और उद्योगों पर नियंत्रण तथा अन्य आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इन उपायों की सफलता केवल आदेश जारी करने से नहीं,बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी से सुनिश्चित होती है। यदि

सफाई,निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और वाहनों के उत्सर्जन की जांच पहले से सुनिश्चित की जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना,स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करना और प्रदूषण कार्रवाई करना दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में पराली जलाने की समस्या का समाधान किसानों पर जुर्माना लगाने भर से नहीं होगा। उन्हें फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सस्ती मशीनें,तकनीकी सहायता,आर्थिक प्रोत्साहन और स्थानीय स्तर पर उपयोग की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। किसानों को समस्या का भागीदार नहीं,समाधान का सहयोगी बनाना होगा।

प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। नागरिकों को निजी वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करने,सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कचरा और पत्तियां न जलाने तथा ऊर्जा की बचत करने जैसे कदम उठाने होंगे। पर्यावरण

संबंधी नियमों के उल्लंघन की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता एवं हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों में भाग लेना भी आवश्यक है। मीडिया,शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को जनजागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि स्वच्छ हवा का महत्व केवल प्रदूषण के चरम पर ही याद न आए। साथ ही, वायु गुणवत्ता के सितंबर-अक्टूबर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। प्रदूषण के स्रोतों की पहचान,औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण, सड़कों की नियमित

सफाई,निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और वाहनों के उत्सर्जन की जांच पहले से सुनिश्चित की जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना,स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करना और प्रदूषण कार्रवाई करना दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में पराली जलाने की समस्या का समाधान किसानों पर जुर्माना लगाने भर से नहीं होगा। उन्हें फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सस्ती मशीनें,तकनीकी सहायता,आर्थिक प्रोत्साहन और स्थानीय स्तर पर उपयोग की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। किसानों को समस्या का भागीदार नहीं,समाधान का सहयोगी बनाना होगा। प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। नागरिकों को निजी वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करने,सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कचरा और पत्तियां न जलाने तथा ऊर्जा की बचत करने जैसे कदम उठाने होंगे। पर्यावरण

अनाज की उपलब्धता से आगे बढ़कर संतुलित,विविध और किफायती आहार सुनिश्चित करना होगा,तभी बनेगा स्वस्थ और संपन्न भारत

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि का आकलन केवल उसकी आर्थिक विकास दर,औद्योगिक उत्पादन या खाद्यान्न भंडार से नहीं किया जा सकता।

राष्ट्र की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना उसके नागरिकों का स्वास्थ्य, पोषण स्तर और कार्यक्षमता है।

भारत ने खाद्यान्न उत्पादन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं,लेकिन अब चुनौती केवल पेट भरने की नहीं,बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने की है। इसी संदर्भ में पर्याप्त प्रोटीन का केंद्रीय विषय बनकर उभरा है। पोषण माह जैसे जनजागरूकता अभियानों का महत्त्व भी इसी व्यापक दृष्टिकोण में निहित है, जहाँ संतुलित आहार, विविध खाद्य पदार्थों और बेहतर पोषण व्यवहार पर जोर दिया जाता है।

प्रोटीन शरीर की वृद्धि,विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। यह मांसपेशियों,त्वचा,उतकों और अनेक जैविक संरचनाओं के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पोषण सुरक्षा की बुनियाद है पर्याप्त प्रोटीन

शरीर में एंजाइम,कई हार्मोन और प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े घटकों के निर्माण में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी कमी केवल शारीरिक कमजोरी तक सीमित नहीं रहती,बल्कि व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। बच्चों के लिए पर्याप्त प्रोटीन विशेष रूप से आवश्यक है,क्योंकि बचपन में शरीर और मस्तिष्क का तीव्र विकास होता है। संतुलित आहार की कमी से बच्चों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है और कुपोषण का जोखिम बढ़ सकता है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है,क्योंकि इस अवधि में शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें बढ़ जाती हैं। पर्याप्त पोषण माँ के स्वास्थ्य और शिशु के समुचित विकास में सहायक होता है।

प्रोटीन का संबंध केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य से नहीं,बल्कि देश की उत्पादकता से भी है। स्वस्थ नागरिक अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षा,रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में निहित है, जहाँ संतुलित आहार, विविध खाद्य पदार्थों और बेहतर पोषण व्यवहार पर जोर दिया जाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि,विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। यह मांसपेशियों,त्वचा,उतकों और अनेक जैविक संरचनाओं के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



की उपलब्धता के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने करोड़ों लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी पर्याप्त कैलोरी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्त्व भी मिल रहे होंगे। घरेलू उपभोग के आँकड़े इस चुनौती को और संकेत करते हैं। वर्ष 2023-24 में ग्रामीण भारत के कुल प्रोटीन सेवन में अनाज का योगदान लगभग 46-47 प्रतिशत बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी आबादी के भोजन में प्रोटीन का स्रोत सीमित खाद्य विविधता पर निर्भर है। अनाज भी प्रोटीन पदान करतें हैं,लेकिन केवल उन्हीं पर निर्भर रहना संतुलित पोषण की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। दालें, दूध,दही,अंडे,सोयाबीन,मेवे और बीज वाले देश में मानव पूँजी का विकास तभी संभव है,जब बच्चों और युवाओं को पर्याप्त पोषण मिले। इस प्रकार प्रोटीन की उपलब्धता सामाजिक कल्याण के साथ-साथ आर्थिक विकास की भी बुनियाद है। भारत में खाद्य सुरक्षा की चर्चा लंबे समय तक गेहूँ,चावल और अन्य अनाजों

दाल,दूध,फल,सब्जियाँ या अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पा रहा,तो उसकी पोषण संबंधी जरूरतें अधूरी रह सकती हैं। प्रोटीन की पर्याप्त खपत के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक महँगाई है। दालों, दूध,अंडों और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों की कीमतें कम आय वाले परिवारों के बजट को प्रभावित करती हैं। ऐसे परिवारों को अक्सर भोजन की मात्रा और गुणवत्ता के बीच कटिन् चुनाव करना पड़ता है। जब घरेलू आय का बड़ा हिस्सा आवास,शिक्षा,परिवहन और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च हो जाता है, तब विविध आहार सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। इसलिए पोषण संबंधी समस्या को केवल व्यक्तिगत पसंद या जागरूकता की कमी के रूप में देखना उचित नहीं है। इसका सीधा संबंध आय, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उनकी कीमतों से भी है।

इस चुनौती का एक महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं और बच्चों का पोषण है। कई परिवारों में महिलाओं की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिलती। गर्भवती महिलाओं,किशोरियों और छोटे बच्चों को विशेष पोषण की आवश्यकता होती है,लेकिन गरीबी, सामाजिक असमानता और जानकारी के अभाव के कारण उनकी जरूरतें अधूरी रह सकती हैं। बच्चों के शुरुआती वर्षों में पोषण उनके शारीरिक विकास और

सीखने की क्षमता पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए पोषण नीतियों में संवेदनशील समूहों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त,भोजन से संबंधित सामाजिक धारणाएँ और जागरूकता की कमी भी समस्या को बढ़ाती हैं। कई बार भोजन को केवल पेट भरने या ऊर्जा प्राप्त करने का साधन माना जाता है। संतुलित आहार में प्रोटीन,वसा,कार्बोहाइड्रेट, विटामिन,खनिज और रेशे की उचित भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। दूसरी ओर,प्रोटीन के अच्छे स्रोतों को केवल मछी खाद्य पदार्थों से जोड़ने की प्रवृत्ति भी प्रचलित है। वास्तव में भुना चना,सत्तू, मूँगफली,विभिन्न दालें और सोया बीन जैसे अपेक्षाकृत किफायती विकल्प भी प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं।

भारत में प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन और पोषण नीति के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। दालों की उत्पादकता बढ़ाने, उन्नत बीज उपलब्ध कराने, किसानों को उचित मूल्य दिलाने और भंडारण तथा वितरण व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू बाजार में आपूर्ति को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करते हू, किसानों को ऐसी फसलों की ओर भी प्रेरित करना चाहिए, जो मिट्टी को उर्वरता, जल संरक्षण और पोषण सुरक्षा में योगदान दें।(सरकारी पोषण कार्यक्रमों को भी भोजन की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से मजबूत बनाना होगा।

गरबे का जोश,शरीर बेहोश

पहले गरबा भक्ति का माध्यम था। लोग माता की आराधना कर कुछ कदम घूमते थे,प्रसाद खाकर घर लौट आते थे। अब गरबा राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बन गया है,जिसमें भक्ति से ज्यादा ड्रेस,डॉप,फोटो और सोशल मीडिया की रीतों का महत्व है। गरबे वाली जोड़ियाँ एक दूसरे को म्हरा सोण रे.गाकर मस्त हो जाती हैं। लो भाई,माता की आरती पाँच मिन्ट में समाप्त। माता रानी भी सोचती होंगी-मेरे भक्तों, मेरी पूजा कर रहे हो या अपने फंतेलोअर्स की संख्या बढ़ा रहे हो? मन ही मन कहती होंगी-बेटा,दर्शन करने आए हो या आर्डिशन देने! नौ दिन तक गरबा खेलने का उत्साह ऐसा कि ऑफिस में फाइलें नाचती हैं और रात में कमर। नगाड़े संग खेल बाजे। की थाप सुनते ही पैरों में बिजली दौड़ती है। उम्र भले ही चालीस पार हो,लेकिन मन कहता है-अभी तो मैं जवान हूँ!शरीर बेचारा आवाज लगाता है-मालिक,जवानी अपनी जगह है!मार घुटनों की भी कोई उम्र होती है! गरबे के मैदान में कोई नागिन डांस कर रहे है,कोई हेलीकॉप्टर की तरह घूम रहा है और कोई ऐसा स्टैप मार रहा है,जिसे देखकर फिजियोथेरेपिस्ट की फीस शेर माँ करते टॉप गेर मा आ जाती है। कुछ लोग तो इस उत्साह में इतने चक्कर लगा लेते हैं कि घर लौटते समय उन्हें ज़ुली या चप्पल पहनने का भी होश नहीं रहता। वे अपने साथी से कहते हैं-पै भई पॉलिथीन में डाल दे यार और गाड़ी तू ही चला,मैं तो पंकर हो गया हूँ। सबसे मजेदार दृश्य तब होता है, जब नौ दिन तक

सोफे पर बैठकर टीवी देखने वाला व्यक्ति गरबे की पहली रात डांस का सुपरस्टार समझने लगता है। दो घंटे तक लगातार घूमने के बाद जब कमर जवाब देती है,तो उसे समझ आता है कि शरीर कोई रिचार्ज होने वाला मोबाइल नहीं है,जिसे सुबह चार्ज करके रात भर चलाया जा सके। अस्पतालों में भी इन दिनों गरबे का असर दिखाई देता है। किसी की कमर में दर्द,किसी की पिंडली में खिंचाव,तो किसी के घुटने में शिकायत! डॉक्टर पूछते हैं,किंतुनी दर्द गरबा किया? मरीज गर्व से जवाब देता है,डॉक्टर साहब, पूरे चार घंटे! डॉक्टर कहते हैं,बच्चा खूब! नौ दिन तक दिन आराम कीजिए। मरीज तुरंत पूछता है,लेकिन डॉक्टर साहब, कल फाइनल राउंड है! डॉक्टर माथा फड़क लेते हैं। उन्हें लगता है कि बीमारी शरीर में कम और गरबे के जुनून में ज्यादा है।

असल समस्या गरबा नहीं,बल्कि जोश में होश खो देना है। ममार शरीर की क्षमता को नजरअंदाज करके लगातार घंटों नाचना समझदारी नहीं है। आखिर माता रानी भी यही चाहेंगी कि उनके भक्त नौ दिन आनंद से गरबा करें और दसवें दिन भंडारा सूत लें। विजयादशमी पर अपनी अकड़ी हुई कमर का दहन न करवाएं! हे भक्तों! गरबा जरूर खेलिए,जमकर खेलिए, इस तरह नहीं कि अगले दिन आपको पिंडली आपको देखकर कहे-

बस मालिक,अब अगले नवरात्रि में मिलेंगे!

संजय एम तरणेकर
 इन्दौर मध्य प्रदेश







बैकुंठपुर से कैलाशपुर तक दशहरे की धूम, धू-धू कर जले रावण के पुतले, जय श्रीराम के जयघोष से गूंजे मैदान

मिनी स्टेडियम में उमड़ा जनसैलाब, विधायक भैयालाल राजवाड़े और कलेक्टर रोचिमा यादव ने किया दहन सलगवां कला में विधायक रेणुका सिंह की मौजूदगी, सोनहत मुख्यालय में आयोजन नहीं होने से मायूसी जय श्रीराम के जयघोष से गूंजे मैदान, बैकुंठपुर-कैलाशपुर में रावण दहन का भव्य नजारा कहीं आतिशबाजी, कहीं अग्निबाण से रावण दहन; सोनहत मुख्यालय में दशहरे का आयोजन न होने से निराशा बैकुंठपुर में हजारों की भीड़, कैलाशपुर में बाल कलाकारों का जलवा, सलगवां कला में भी दशहरे की धूम असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव, बैकुंठपुर से ग्रामीण अंचलों तक दशहरे का उल्लास

मिनी स्टेडियम में उमड़ा जनसैलाब, कैलाशपुर में राम-लक्ष्मण के अग्निबाण से जला रावण



सोनहत मुख्यालय में आयोजन नहीं होने से लोगों में मायूसी

सोनहत विकासखंड के कैलाशपुर और सलगवां कला में जहां विजयादशमी पर रावण दहन के आयोजन हुए, वहीं सोनहत मुख्यालय में इस वर्ष कार्यक्रम नहीं होने से स्थानीय लोगों में निराशा देखने को मिली, मुख्यालय में रावण दहन नहीं होने के कारण लोगों को अपने ही क्षेत्र में दशहरे का पारंपरिक आयोजन देखने का अवसर नहीं मिला, दशहरा बच्चों और युवाओं के लिए विशेष उत्साह का पर्व होता है। परिवार और ग्रामीण एक साथ जुटकर रावण दहन देखते हैं तथा धार्मिक परंपराओं में भाग लेते हैं, ऐसे में मुख्यालय में आयोजन नहीं होने से सामूहिक उत्सव की कमी महसूस की गई, कई ग्रामीण अपनी सुविधानुसार कैलाशपुर, सलगवां कला और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए, मुख्यालय में आयोजन की अनुपस्थिति स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय रही, ग्रामीणों को उम्मीद है कि भविष्य में सामूहिक पहल के माध्यम से सोनहत मुख्यालय में भी रावण दहन जैसे पारंपरिक आयोजन को फिर शुरू करने का फैसला किया जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों को अपने मुख्यालय में ही विजयादशमी का उत्सव देखने और उसमें भाग लेने का अवसर मिल सके।

सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुए आयोजन

विजयादशमी के अवसर पर कैलाशपुर और सलगवां कला में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा, आयोजन स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखने और कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल की मौजूदगी रही, धार्मिक उत्साह और जनभागीदारी के बीच कार्यक्रम संपन्न हुए, बैकुंठपुर से लेकर सोनहत विकासखंड के ग्रामीण अंचलों तक विजयादशमी के आयोजनों ने धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक एकता की झलक प्रस्तुत की, बैकुंठपुर में तीनों पुतलों का दहन, स्थानीय कलाकारों का सम्मान, कैलाशपुर में बाल कलाकारों की प्रस्तुतियां और सलगवां कला में विधायक रेणुका सिंह की मौजूदगी में हुआ रावण दहन पर्व के प्रमुख आकर्षण रहे, हालांकि सोनहत मुख्यालय में आयोजन नहीं होने की कमी लोगों को खलती रही, लेकिन आसपास के गांवों में हुए कार्यक्रमों ने क्षेत्रवासियों को विजयादशमी मनाने का अवसर दिया, पर्व का संदेश यही रहा कि सत्य, मर्यादा और सदाचार को अपनाकर अहंकार तथा बुराईयों पर विजय प्राप्त की जाए।

देवेंद्र तिवारी ने सहयोगियों और आयोजनकर्ताओं का किया सम्मान

कोरिया सर्व विकास समिति के संरक्षक देवेंद्र तिवारी ने दशहरा महोत्सव को सफल बनाने में योगदान देने वाले सहयोगियों और आयोजनकर्ताओं का सम्मान किया, इनमें समिति के सचिव विवेक गुप्ता, राधे वेलफेयर सोसाइटी के अभय बडेरिया और उनकी टीम सहित आयोजन की तैयारियों, व्यवस्थाओं तथा संचालन में सहयोग करने वाले लोग शामिल रहे, देवेंद्र तिवारी ने समिति के सदस्यों, कलाकारों, स्वयंसेवकों, सहयोगी संस्थाओं और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया, उन्होंने विजयादशमी को केवल रावण के पुतले के दहन तक सीमित न मानते हुए इसे अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने और सत्य, सदाचार तथा मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर बताया, उन्होंने सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक संरक्षण और जनभागीदारी की भावना से ऐसे आयोजनों को आगे भी जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई, बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी ने बैकुंठपुर के दशहरा महोत्सव को धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ सामुदायिक सहभागिता का रूप दिया।

सलगवां कला में विधायक रेणुका सिंह की मौजूदगी में रावण दहन

सोनहत विकासखंड के सलगवां कला में भी विजयादशमी का पर्व उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया, यहाँ आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं, उनकी मौजूदगी में हुए आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के गांवों से पहुंचे लोग शामिल हुए, कार्यक्रम स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी और पारंपरिक उत्साह के साथ विजयादशमी मनाई गई, रावण दहन के दौरान जय श्रीराम के जयघोष लगाए गए, इस अवसर पर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में दशहरा धार्मिक आस्था के साथ मेल-मिलाप और सामूहिक सहभागिता का अवसर भी होता है, सलगवां कला में लोगों की भागीदारी ने पर्व के प्रति इसी उत्साह को प्रदर्शित किया।

बच्चों और गायन-वादन टीमों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया, स्थानीय कलाकारों को पहचान दिलाने और उन्हें बड़े मंच से जोड़ने की पहल को आयोजन की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखा गया, विधायक भैयालाल राजवाड़े और कलेक्टर रोचिमा यादव ने महोत्सव के आयोजन तथा स्थानीय प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की,

आयोजन ने धार्मिक उत्सव के साथ स्थानीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर भी उपलब्ध कराया।

कैलाशपुर में सनातन गौरव मंच का आयोजन, बाल कलाकारों ने मोहान कैलाशपुर में सनातन गौरव मंच के तत्वावधान में विजयादशमी पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, धार्मिक गतिविधियों के

असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व कोरिया जिले में धार्मिक आस्था, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया, जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के मिनी स्टेडियम से लेकर सोनहत विकासखंड के कैलाशपुर और सलगवां कला तक दशहरे की धूम देखने को मिली। कहीं विशालकाय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन हुआ, तो कहीं भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूप में सजे कलाकारों ने अग्निबाण चलाकर रावण का अंत किया, जय श्रीराम के जयघोष, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आतिशबाजी के बीच लोगों ने विजयादशमी का पर्व मनाया, हालांकि, सोनहत मुख्यालय में इस वर्ष रावण दहन का आयोजन नहीं होने से स्थानीय लोगों में मायूसी भी रही, बैकुंठपुर में कोरिया सर्व विकास समिति के तत्वावधान में मिनी स्टेडियम में आयोजित भव्य दशहरा महोत्सव में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे, कार्यक्रम में विधायक भैयालाल राजवाड़े और कलेक्टर रोचिमा यादव ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया, वहीं, सोनहत विकासखंड के सलगवां कला में विजयादशमी के अवसर पर कैलाशपुर और सलगवां कला में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा, आयोजन स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखने और कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल की मौजूदगी रही, धार्मिक उत्साह और जनभागीदारी के बीच कार्यक्रम संपन्न हुए, बैकुंठपुर से लेकर सोनहत विकासखंड के ग्रामीण अंचलों तक विजयादशमी के आयोजनों ने धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक एकता की झलक प्रस्तुत की, बैकुंठपुर में तीनों पुतलों का दहन, स्थानीय कलाकारों का सम्मान, कैलाशपुर में बाल कलाकारों की प्रस्तुतियां और सलगवां कला में विधायक रेणुका सिंह की मौजूदगी में हुआ रावण दहन पर्व के प्रमुख आकर्षण रहे, हालांकि सोनहत मुख्यालय में आयोजन नहीं होने की कमी लोगों को खलती रही, लेकिन आसपास के गांवों में हुए कार्यक्रमों ने क्षेत्रवासियों को विजयादशमी मनाने का अवसर दिया, पर्व का संदेश यही रहा कि सत्य, मर्यादा और सदाचार को अपनाकर अहंकार तथा बुराईयों पर विजय प्राप्त की जाए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूज्य माता हासी देवी जी के सम्मान में जारी किया 200 रुपए का स्मारक सिक्का...

युवा बड़े सपने देखें, अपनी सफलता को समाज और राष्ट्र की सेवा से जोड़ें : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू



रायपुर, 22 अक्टूबर 2026। युवा बड़े सपने देखें, अपने विचारों को व्यापक बनाएं और अपनी सफलता को समाज एवं राष्ट्र की सेवा से जोड़ें। परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक युवा के भीतर कुछ नया करने, बेहतर बनाने और अपनी पहचान स्थापित करने की ललक होनी चाहिए। जब युवाओं के व्यक्तिगत प्रयास सामूहिक और राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ेंगे, तभी देश की प्रगति का मार्ग और अधिक प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में नुआखाई के अवसर पर आयोजित 'सेवा सम्मान पर्व एवं युवा प्रबोधन' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने नुआखाई की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नुआखाई मिलन केवल एक सांस्कृतिक समारोह नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध परंपराओं, आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता का उत्सव है। ऐसे आयोजन हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने और भारतीय जीवन मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि नुआखाई हमारी कृषि परंपरा को सहेजने, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और समुदायिक



विकसित भारत के लिए महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी

राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। देश की आधी आबादी को आगे बढ़ाए बिना राष्ट्र पूरी क्षमता के साथ प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने महिलाओं से देश और समाज के कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने पुरुषों, विशेषकर युवाओं से कहा कि वे अपनी बहनो और बेटियों को ऐसा वातावरण और अवसर प्रदान करें, जिसमें वे बिना किसी बाधा के अपने सपनों को साकार कर सकें। महिलाओं के प्रति सम्मान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी सोच, व्यवहार और दैनिक आचरण में भी दिखाई देना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में हो रहे सकारात्मक बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों तथा युवाओं की दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर प्रदेश के युवा नवसतवादी के भटकाने से मुक्त होकर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां कभी आतंक का अंधेरा था, वहां आज विकास का उजियारा फैल रहा है। इस परिवर्तन से न केवल युवाओं और उनके परिवारों का कल्याण हो रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के विकास को भी गति मिल रही है।

भावना को मजबूत करने का पर्व है। अन्न केवल हमारी भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि किसान भाई-बहनो के परिश्रम, धरती की उदारता और प्रकृति के अनमोल उपहार का प्रतीक है। अन्न का सम्मान करना, किसानों के योगदान को स्वीकार

करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डप में पूज्य माता हासी देवी जी के सम्मान में 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर

ज्ञान के साथ विनम्रता, महत्वाकांक्षा के साथ नैतिकता और सफलता के साथ सेवा-भाव जोड़ें युवा : मुर्मू

राष्ट्रपति मुर्मू ने युवाओं से कहा कि वे जीवन में सीखना कभी बंद न करें। पुस्तकें पढ़ें, प्रश्न पूछें, नई चीजों को समझें और अपने ज्ञान एवं कौशल को निरंतर विकसित करें। जीवन में लक्ष्य तय करें और चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करें। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा हैं। असफलता से निराशा होने के बजाय उससे सीखकर स्वयं में सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को ज्ञान के साथ विनम्रता, महत्वाकांक्षा के साथ नैतिकता और सफलता के साथ सेवा-भाव को जोड़ना चाहिए। अपना ज्ञान किसी जरूरतमंद के काम आए, आपकी प्रतिभा किसी समस्या का समाधान करे और आपकी सफलता समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बने, तभी उपलब्धि की वास्तविक सार्थकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र का निर्माण केवल बड़े निर्गुणों से नहीं होता, बल्कि करोड़ों नागरिकों के छोटे-छोटे ईमानदार प्रयासों से होता है। प्रत्येक युवा जो भी कार्य करे, उसे ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करे। ये गुण विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं के योगदान को और शक्ति बनाएंगे।

राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उपस्थित थे। पूज्य शतापी दरबार रायपुर की 5 वीं पीठाधीश्वर माता साहिब हासी देवी की 200 वीं जयंती पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। सिंधी विभूति के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी होना समाज के लिए ऐतिहासिक मौका था। यह देश-विदेश में रहने वाले करोड़ों सिंधी लोगों के लिए गर्व का विषय है। स्मारक सिक्के का अनावरण होने के बाद श्रद्धालु और सिक्का संग्राहक इसे शतापी दरबार की अलग-अलग इकाइयों के माध्यम से बुक कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जारी इस विशेष सिक्के पर पूज्य माता हासी देवी जी की छवि अंकित है। सिक्के के एक ओर अशोक स्तंभ का

सिंह शीर्ष और 200 रुपये का मूल्यवर्ग दर्शाया गया है। इस स्मारक सिक्के के माध्यम से उनके जीवन, विचारों और आध्यात्मिक योगदान को भावी पीढ़ियों तक सकारात्मक रूप से प्रसारित किया गया है। कार्यक्रम में स्वागत उद्घोषण पूज्य शतापी दरबार रायपुर के पीठाधीश्वर संत डॉ. युधिष्ठिर लाल जी ने दिया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी, सांसद वृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, सीनियर सीनियर, मोतीलाल साहू, मुख्य सचिव विकासशील, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना सहित वरिष्ठ अधिकारी, पूज्य शतापी दरबार के सदस्य सहित देशभर से आए हुए जनप्रतिनिधि और सिंधी समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का छत्तीसगढ़ से गहरा आत्मीय संबंध है। प्रदेशवासियों के मन में उनके प्रति अपार आदर और आत्मीयता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू जी का संपूर्ण जीवन संघर्ष, सादगी, सेवा, शिक्षा और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक मिसाल है। ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की उनकी जीवन यात्रा विशेष रूप से देश की बेटियों, युवाओं तथा जनजातीय और ग्रामीण अंचलों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनका मार्गदर्शन प्रदेश के युवाओं को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नुआखाई हमारी समृद्ध कृषि संस्कृति, नई फसल के स्वागत और धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सदियों पुराने सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध हैं।

युवा शक्ति को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा विकसित छत्तीसगढ़ : साय

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की निर्णायक भूमिका होगी। राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवा शक्ति को केंद्र में रखकर शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, नवाचार और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए गौदम, कुनकुरी, जाजगीर-चापा, मनेन्द्रगढ़ और कवर्धा में पांच नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, जहां प्रतिवर्ष लगभग चार हजार युवाओं को आधुनिक तकनीक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा।

नुआखाई सामाजिक एकता और सेवा भावना का पर्व : राज्यपाल रमन डेका

राज्यपाल रमन डेका ने प्रदेशवासियों को नुआखाई जुहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व केवल नई फसल के आगमन की खुशी मनाने का अवसर नहीं, बल्कि धरती माता के प्रति कृतज्ञता, किसानों के परिश्रम के सम्मान और मिल-जुलकर खुशियों बांटने का उत्सव है। यह हमारी समृद्ध कृषि संस्कृति, सामाजिक एकता और आपसी सहयोग की परंपरा को मजबूत करता है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति को प्रदेश के लिए सौभाग्य और प्रेरणा का अवसर बताते हुए कहा कि उनका संघर्ष, सादगी, समर्पण और सेवाभाव हम सभी के लिए प्रेरक है। उन्होंने युवाओं से सेवा को अपने जीवन का स्वभाव बनाने और नशे एवं भटकाने से दूर रहकर ज्ञान, कौशल और नवाचार के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में बड़ा फेरबदल 84 कर्मचारियों का हुआ तबादला, जारी हुई सूची

रायपुर, 22 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर बड़ा फेरबदल किया गया है। विभाग ने अलग-अलग संवर्गों के कुल 84 कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस सूची में मानचित्रकार से लेकर सहायक ग्रेड-1 और सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी शामिल हैं। आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को अब नई जगह पर जिम्मेदारी संपालनी होगी।

तीन श्रेणियों के कर्मचारियों के नाम शामिल

जारी तबादला सूची के अनुसार, कुल 84 कर्मचारियों में 29 मानचित्रकार, 14 सहायक ग्रेड-1 और 41 सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी शामिल हैं। मानचित्रकारों में सिविल, विद्युत और यांत्रिकी संवर्ग के कर्मचारी भी हैं। विभागीय स्तर पर किए गए इस फेरबदल के तहत कर्मचारियों को नई पदस्थापना दी गई है।

नई जगह संपालना होगा कार्यभार

तबादला आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस प्रशासनिक बदलाव से विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और तैनाती में बदलाव होगा। लोक निर्माण विभाग राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े कार्यों के लिए महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में



विभागीय कार्यालयों में कर्मचारियों की पदस्थापना का असर प्रशासनिक कामकाज पर भी पड़ सकता है।

कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया कदम

लोक निर्माण विभाग में किए गए इन तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। विभागीय कामकाज में बेहतर समन्वय, कर्मचारियों की उपलब्धता और कार्यों के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है।

रायपुर में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन साइकिल रैली निकाली, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

रायपुर, 22 अक्टूबर 2026। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने और मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने के आरोप लगाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत आजाद चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा से हुई। यहां से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आभापारा और तेलधानी नाका होते हुए अंबेडकर अस्पताल पहुंचे। रैली का समापन डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास हुआ।

विकास उपाध्याय बोले...देशभर में आंदोलन कर रही कांग्रेस

प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस देशभर में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर



आंदोलन कर रही है। इसके तहत अलग-अलग जिलों में साइकिल यात्रा, धरना और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर चुनावी अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।

13 कटेड नाम हटाने का दावा

विकास उपाध्याय ने कहा कि, देशभर में 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए

गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अलग-अलग राज्यों में चुनावी फायदा उठाने के लिए वोट चोरी की। उन्होंने भाजपा के निर्वाचित विधायकों और सांसदों के चुनाव पर भी सवाल उठाए।

जनता के सामने मुद्दा उठाने की बात कही : रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि, पार्टी वोट चोरी के मुद्दे को जनता के सामने लाना चाहती है। पार्टी नेताओं ने मतदाता सूची में

बदलाव और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग कि लेकिन अब तक उन्होंने ने इस्तीफा नहीं दिया है। वोट चोरी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।

राष्ट्रगान के बाद किया प्रदर्शन

अंबेडकर प्रतिमा के पास कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान किया। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के आरोपों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।

बिलासपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

गोंडवाना की बग़ाय इंटरसिटी से आए, संघ की बैठक में शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ संगठन में बदलाव की चर्चा

बिलासपुर, 22 अक्टूबर 2026। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे हैं। गुरुवार दोपहर रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच उतरने के बाद वे कोनी स्थित सरस्वती आवासीय विद्यालय पहुंचे। यहां वे संघ के बौद्धिक वर्ग और महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। कार्यक्रम में युवाओं को संगठन से जुड़ने और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के टिप्स दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मोहन भागवत गोंडवाना एक्सप्रेस से शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचने वाले थे।

लेकिन वे इंटरसिटी एक्सप्रेस से तय समय से पहले बिलासपुर पहुंचे। कुल 23 अक्टूबर को प्रांत कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें छत्तीसगढ़ में संघ के प्रांत प्रमुख का पद समाप्त करने पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। कोनी में बौद्धिक वर्ग में संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित अन्य आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। डॉ. भागवत देश और समाज से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही भविष्य की रूपरेखा पर मार्गदर्शन देंगे। इसके बाद एक दौर की बैठक होगी।



ABVP और BJYM के युवाओं को दे सकते हैं टिप्स

बताया जा रहा है कि देश में युवाओं के आंदोलनों को देखते हुए आरएसएस आने वाले समय में 40 साल से कम उम्र के लोगों को संगठन से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके तहत आरएसएस के साथ-साथ अन्य आनुषंगिक संगठनों में भी युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। संघ के वर्गों की तरह अलग-अलग गतिविधियों के जरिए युवाओं को जोड़ने की योजना है। ऐसे में मोहन भागवत संघ से जुड़े युवा संगठनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं को टिप्स दे सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में संघ के प्रांत प्रमुख का पद से सकता है समाप्त

संघ से जुड़े लोगों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में फिलहाल आरएसएस के प्रांत प्रमुख का पद है। उनके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में अखिल भारतीय स्तर की बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रांत को दो हिस्सों में बांटने पर चर्चा हो सकती है। इसके तहत रायपुर और बिलासपुर विभाग बनाए जाएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ प्रांत को 11 विभागों में बांटा गया है। भाजपा के बाद रायपुर में 6 और बिलासपुर में 5 विभाग शामिल होंगे। इससे संघ के कामकाज का विकेंद्रीकरण होगा। इसके साथ ही प्रांत प्रमुख सहित कई मौजूदा पद समाप्त हो सकते हैं, उसके साथ पद भी बनाए जाएंगे। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत इस विषय पर पदाधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। डॉ. मोहन भागवत दूसरे दिन छत्तीसगढ़ प्रांत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक होंगे। इसमें बिलासपुर नगर के 11 उपनगरों सहित पूरे छत्तीसगढ़ के संघ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस बैठक में भाजपा सहित संघ के अन्य आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

धमतरी में पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या

धमतरी, 22 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शहर से लगे मुजगहन गांव में दो युवकों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में गांव के पूर्व सरपंच के बेटे दीपांशु साहू की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद दोनों को खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। पुलिस ने मामले में 3-4 संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम मुजगहन की है। जानकारी के मुताबिक, बीती रात कुछ लोगों ने दीपांशु साहू और उसके साथी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पूर्व सरपंच के बेटे दीपांशु साहू ने दम तोड़ दिया। दूसरे युवक का इलाज जारी है। सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी के मुताबिक, मामले में 3-4 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

भिलाई स्टील प्लांट की रेल मिल पर अडाणी की नजर बिक्री की खबरों को अफवाह बताने पर पूछा- पीआर विभाग को खंडन का अधिकार किसने दिया : भूपेश बघेल

दुर्ग-भिलाई, 22 अक्टूबर 2026।

छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट (भिलाई स्टील प्लांट) को बेचने की खबरों को प्रबंधन की ओर से अफवाह और भ्रामक बताया जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट के जनसंपर्क विभाग को बिक्री संबंधी खबरों का खंडन जारी करने का अधिकार किसने दिया? क्या यह बयान भारत सरकार की अनुमति से जारी किया गया है? बिक्री का फैसला भारत सरकार करती है। बघेल ने आरोप लगाया कि, अडाणी समूह की नजर भिलाई स्टील प्लांट की रेल मिल पर है और प्लांट को खरीदने की कोशिश की जा रही है। बोले- किसकी अनुमति से जारी किया गया बयान : भूपेश बघेल ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट की बिक्री का फैसला भारत सरकार के स्तर पर होता है। यदि



स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का प्रवक्ता है और न ही इसका मंत्रालय का। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट करने को कहा कि बिक्री की खबरों को खारिज करने वाला बयान भारत सरकार की अनुमति से जारी किया गया था या नहीं। बघेल ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट की बिक्री का फैसला भारत सरकार के स्तर पर होता है। यदि दावों का खंडन किया है।

बयान बिना अनुमति जारी किया गया है, तो संबंधित अधिकारी को भिलाई की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने 18 अक्टूबर को जारी बयान में संयंत्र की बिक्री से जुड़ी खबरों को असत्य और भ्रामक बताया था। प्रबंधन के मुताबिक, इसका मंत्रालय और पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इन दावों का खंडन किया है।



A Celebration of Tribal Heritage,
Faith and People's Participation

MURIA DARBAR & BASTAR DUSSEHRA

Friday, 23 October 2026

Time : 12:45 PM onwards
VENUE : LAL BAGH GROUND, JAGDALPUR, BASTAR



**CHHATTISGARH EXTENDS
A WARM WELCOME TO**

Smt. Droupadi Murmu

Hon'ble President of India



Shri Vishnu Deo Sai

Hon'ble Chief Minister, Chhattisgarh



SCAN THE
QR
TO JOIN US



Visit us : [f](https://www.facebook.com/ChhattisgarhCMO) [X](https://www.twitter.com/ChhattisgarhCMO) [@](https://www.instagram.com/ChhattisgarhCMO) [/ChhattisgarhCMO](https://www.youtube.com/ChhattisgarhCMO) [f](https://www.facebook.com/DPRChhattisgarh) [X](https://www.twitter.com/DPRChhattisgarh) [@](https://www.instagram.com/DPRChhattisgarh) [/DPRChhattisgarh](https://www.youtube.com/DPRChhattisgarh) www.dprcg.gov.in